(a) whether Government propose to involve States in framing the employment policies;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Planning Commission has preparped a draft proposal in this regard for implementation during the Ninth Five Year Plan; *

(d) if so, the details thereof;

(e) the number of employment opportunities created in the organised sectors, particularly in the North-Eastern States, during the last three years, State-wise; and

(f) the number of employment opportunities likely to be created during 1997-98?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DE-HARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) States are involved in framing employment policies and programmes.

(c) and (d) The approach to 9th Plan gives direction for employment policy. Priority is given to Agriculture and Rural Development with a view to generating adequate productive employment and eradication of poverty.

(e) and (f) Employment in Organised Sector as of 31st March in the years 1994, 1995 and 1996 is given in the table below:

Employment Organised Sector (in million)

	1994	1995 *	1996
1. Assam	1.07	1.09	1.15
2. Arunachal Pradesh	—	—	0.07
3. Manipur	0.07	0.08	0.08
4. Meghalaya	0.07	0.07	0.07
5. Mizoram	0.04	0.04	0.04
6. Nagaland	0.07	0.07	0.07
7. Tripura	0.11	0.11	0.11
All India	27.38	27.53	27.64

Source : D.G.E.&T., Ministry of Labour.

Note : The term Employment in Organised Sector is defined by DGE&T as employment in all the establishments in the Public Sector irrespective of the size of employment and non-agricultural establishments in private sector employing 10 or more persons.

Estimates of employment opportunities likely to be created in 1997-98 are not available.

गरीबी रेखा से नीचे लोग

278. **श्री इकबाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या यह सच है कि स्वतंत्रता- प्राप्ति के पचास वर्षों बाद भी देश में लगभग 35 करोड़ लोग अभी तक गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गरीबी के अब तक उनमूलन नहीं किए जा सकने के क्या कारण हैं:

(ग) क्या यह भी सच हैं कि सरकार इस मोर्चे पर पूर्णत: विफल रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में गरीबी के उन्मूलन हेतु बनाई गयी नवीनतम कल्याण याजनाओं के नाम क्या-क्या हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राजय मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) योजना आयोग ने 1993-94 में देश में गरीबों की संख्या 32 रोड़ होने का अनुमान लगाया हैं।

(क) और (ग) प्रति व्यक्ति खपत वृद्धि से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत 1977-78 में 51.32 प्रतिशत से कम होकर 1993-94 में 35.प्रतिशत हो गया हैं और गरीबों की संख्या 1977-78 में 32.9 करोड़ से कम होकर 1993-94 में 32 करोड़ हो गयी है।

(ख) गरीबों की जीवन दशा और आय सुधारने के लिए नेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, गांगा कल्याण योजना, गरीबों के लिए शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्सक्रमों से लाभार्थियों की आय में सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

देश की विकास संबंधी संभाव्यता

279. **श्री राम जेठमलानी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1997 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी खबर "इंडिया हैज थर्ड बिगेस्ट, ग्रोथ पोर्टिशियल इम द वर्ल्ड" की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे विकास कर पाने की क्षमता है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) सरकार ने उस संभावित विकास की क्षमता को विकसित कर उसे उपभोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेशवर सवनूर) : (क) और (ख) जी, हां, अखबार में छपी खबर विश्व आर्थिक फोरन, जोकि जिनेवा में व्यापार संगठित इनुसंधान संस्था हैं, के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक सम्भावित विकास की क्षमता वाले देशों में अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरे स्थान पर था।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत के आर्थिक विकास की समग्र दर की परिकल्पना की गई हैं। निवेश दर को 28.6% तक बढ़ाकर तथा विकासन्मुख नीतियों का अनुसरण करके उक्त विकास प्राप्त किए जाने की योजना बनायी गई हैं।

Constitutional status to the Planning Commission

280. SHRI NILOTPAL BASU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: by when Giovernment arc going to bring a Bill in order to give Constitution al and statutory status to the Planning Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DE-HARESHWAR SAVANOOR): There is no such proposal under consideration, at present.

Satellite Communication Policy

281. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appearing in the Indian Express dated the 13th June, 1997, captioned "rent on Indian Satellite or buy one if you can";

(b) if so, the details thereof; and

(c) the proposed satellite communication policy of the country in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINIS TRY OF PARLIAMENTARY AF FAIRS (SHRI S.R. BALASUBARAMONIYAN): (a) Yes, Sir.

(O) and (c) Satellites are used extensively for telephony, data, T.V. and Sound broadcasting and Mobile services.